E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(2): 19-22
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 13-05-2021
Accepted: 17-06-2021

डॉ. पूनम अग्रवाल
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, मदर टेरेसा मेमोरियल महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. पूनम अग्रवाल
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, मदर टेरेसा मेमोरियल महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत

तेलंगाना राज्य के निर्माण में तेलंगाना राष्ट्र समिति का योगदान और इसका राजनीतिक भविष्य

डॉ. पूनम अग्रवाल

सारांश
नवीन राज्यों का निर्माण एक सहज और सतत प्रक्रिया है, जो लगभग हर देष के इतिहास का भाग है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय को राज्यों के गठन के लिए विषिष्ट माना जाता है क्योंकि देष पुनर्गठन के एक भीषण चक्रव्यूह में फँस गया था जिसमें देष के लगभग प्रत्येक भाग से नवीन राज्य की माँग सिर उठा रही थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक और कूटनीतिक समझ ने इस दुरुह कार्य को लगभग सरल बना दिया था। राज्यों के अंतिम पुनर्गठन के पश्चात भी इन माँगों को पूरी तरह से नकारना संभव नहीं हुआ है और तेलंगाना इसी कड़ी में नवीन राज्य के रूप में जुड़ गया है। तेलंगाना के राज्य बनने की प्रक्रिया में तेलंगाना राष्ट्र समिति राजनीतिक दल की भूमिका को लगभग शतप्रतिषत माना जाता है क्योंकि इस दल के निर्माण का प्रथम और अंतिम उद्देष्य तेलंगाना का निर्माण ही था। सही समय पर लिए गए राजनीतिक निर्णयों ने इस दल को हाषिए से केन्द्र में ला दिया। के. चन्द्रषेखर राव के लगातार समर्थन बदलने के माध्यम से केन्द्र पर दबाव की रणनीति ने इस कार्य को सफल बना दिया। तेलंगाना के निर्माण के बाद भी तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक के. चन्द्रषेखर राव की बुद्धिमतापूर्ण राजनीति और निरन्तर लोकलुभावन नीतियों ने इस दल को प्रासंगिक बनाए रखा है।

मूल शब्दः तेलंगाना, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), नवीन राज्य, चुनाव, उपचुनाव, राजनीति

प्रस्तावना
विभाजन पूर्व के आंध्र प्रदेष में तेलंगाना क्षेत्र भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अनेक दषकों तक भी आंध्र प्रदेष के साथ अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाया। तेलंगाना का सामाजिक ताना–बाना शेष आंध्र प्रदेष से भिन्न ही बना रहा। तेलंगाना ने लंबे समय तक अपनी भाषा संबंधी भिन्नता को बनाए रखा। तेलंगाना क्षेत्र के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत के बचाने के प्रयास में अलग राज्य की परिकल्पना को हृदय में संजो कर रखते रहे।

तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन
27 अप्रेल 2001 को राव ने विधानसभा आंध्रप्रदेष के उपाध्यक्ष पद और टीडीपी विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अलग राज्य ही इसका एकमात्र समाधान है। अप्रेल 2001 में उन्होंने तेलंगाना अभियान के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का गठन किया।
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का उदय इसके अत्यधिक गहरे असंतोष और वंचितता से हुआ। वास्तव में, पृथक राज्य की माँग का आंदोलन विकास के नवउदारवादी आदर्षप्रारूप के गर्भ में आकार ले रहा था। इसलिए माँग उस समय आई जब परिपक्व होती वैकल्पिक मूर्त स्थितियाँ तेलंगाना आत्म पहचान के पुनर्जीवन का आकार ले रही थी जो लगभग दो दषक से सुषुप्त और दमित रही। ये चंद्रषेखर राव थे जिन्होंने उपक्षेत्र के मनोभाव को पहचाना और इसके एक राजनीतिक अभिव्यक्ति मार्ग दिया। तेलंगाना के लोगों का एक बड़ा अंष इस माँग के पक्ष में था और 2004 के चुनावों तक यह एक राजनीतिक बल बन गया। इस प्रवृत्ति को जानकर कांग्रेस दल जो कि टीडीपी को सत्ता से हटाने के लिए हताष थी, ने गठबंधन के निहितार्थों और परिणामों को ठीक प्रकार से माने बिना ही टीआरएस के साथ गठबंधन बना लिया। कांग्रेस दल जो कि स्वतंत्रता के पष्चात से ही अवसरवादी रहा है, ने निष्चयपूर्वक कहा कि यह आर्थिक नीतियों को पुनरावलोकन करेगी और किसी भी परिस्थिति में विष्व बैंक के दबाव के आगे नहीं झुकेगी। इसने चंद्रबाबू नायडू को विष्व बैंक का दास बताया। इसने नक्सली दलों के साथ शांति वार्ता का वादा भी किया। कांग्रेस नेता वाईएस राजषेखर रेड्डी ने ग्रामीण जनसमूहों और कृषकवर्ग में यह विष्वास डालने के लिए 2004 में ग्रामीण आंध्र प्रदेष में पदयात्रा की कि कांग्रेस दल कृषि समस्याओं पर अत्यधिक ध्यान देगा।

इन यात्राओं में तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित थे और ये यात्राएँ टीआरएस के साथ संचालित की गई थी। कांग्रेस दल ने चुनाव जीता।[1]

टीआरएस के राजनीतिक गठबंधन

2004 के चुनावों में राव टीआरएस सदस्य के रूप में सिद्दीपेट विधानसभा क्षेत्र और करीमनगर लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए। टीआरएस ने 2004 के आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन में भाग लिया और राव उन पाँच टीआरएस विधायकों में शामिल थे जो सांसद बने।

यह टिप्पणी की जा सकती है कि चुनावी द्वंद्व कभी भी टीआरएस का सुदृढ़ दुर्ग नहीं रहा। यह इसलिए था क्योंकि अपने शक्तिषाली मताधार और संगठनात्मक संरचना के कारण कांग्रेस और टीडीपी ने राज्य में चुनावी क्षेत्र को बाँट रखा था। टीआरएस ने आंदोलन–अभिकेंद्रित दल होने के दावे के उपरांत भी, कभी भी चुनावी राजनीति को छोड़कर लोकप्रिय लामबंदी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। यह अतिषयोक्ति नहीं है कि 2004 और उसके पष्चात् 2009 में टीआरएस का चुनावी प्रदर्षन मुख्य रूप से उसके क्रमषः कांग्रेस और टीडीपी के साथ गठबंधन का परिणाम था। वास्तव में पिछले दषक के दौरान, गैर दलीय व्यक्तियों साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा तेलंगाना ध्येय के लिए स्वायत्त लामबंदी हुई है। उनके टीआरएस के साथ संबंध कभी भी न करीबी रहे और न सरल रहे। उन्होंने सदैव टीआरएस को पक्ष में जनमत तैयार करने और चुनावी राजनीति के प्रमुख सिद्धांत पर जोर देने के कारण नीचा दिखाया है क्योंकि इन्होंने किसी भी सामाजिक दृष्टि के बिना ही तेलंगाना का निरूपण एक भौगोलिक अस्तित्व के तौर पर किया और निस्संदेह, वेलम्मा और रेड्डी भद्रजनों का संकीर्ण सामाजिक आधार है जो टीआरएस में प्रभावी है। इस गंभीर कमियों और चूकों को टीआरएस नेतृत्व के द्वारा सुधारना तो दूर संबोधित करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं था। इन कारणों से टीआरएस दृढ़ और स्वायत्त राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित नहीं हो सकी जो कि स्वयं अपने स्तर पर चुनाव लड़ सके। फिर भी तीक्ष्ण रूप से ध्रुवीकृत और रूचि से लड़े गए चुनावी मैदानों में टीआरएस ने अपने आप को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जो कांग्रेस और टीडीपी जैसे अन्य प्रभावी दलों का भाग्य खराब कर सके। इसे भूत काल के चुनावों में गठबंधन के प्रति उनकी उत्सुकता से समझाया जा सकता है।[2]

टीआरएस कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन सरकार का हिस्सा थी। दल ने बाद में गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया क्यों कि राव का खयाल था कि गठबंधन एक पृथक तेलंगाना राज्य के समर्थन को लेकर गंभीर नहीं था।[3] 2004 में राव ने लोकसभा चुनाव लड़ा और केंद्र में यूपीए–1 सरकार में श्रम एवं नियोजन केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने 2006 में इस्तीफा दे दिया। 2009 में राव ने महबूबनगर लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। टीआरएस दल ने टीडीपी नीत विपक्ष गठबंधन के भाग के तौर पर आम चुनावों में भाग लिया।

उपचुनाव एवं भविष्य की संभावनाएँ

टीआरएस ने गठबंधन की राजनीति से अपने राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं को टटोल लिया था। तेलंगाना आंदोलन के प्रसंग में जनभावना को विलोड़ित करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए त्यागपत्र की त्यागमयी विचारधारा के माध्यम से जनमानस में गहरी पैठ बनाने के लिए टीआरएस ने अनेक बार उपचुनावों का खेल खेला जिसके परिणाम मिश्रित रहे। युवा व्यक्तियों की आत्महत्या के उत्तेजक प्रकरण पर त्यागपत्र के मामले में टीआरएस को आषातीत सफलता मिली थी।

पृथक राज्य के ध्येय के लिए अधिकांषतः छात्रों– युवा व्यक्तियों की आत्महत्या की श्रंखला के लिए गंभीरता दिखाने की भूमिका के रूप में अपने पदों से 12 विधायकों द्वारा त्यागपत्र देने के कारण जुलाई 2010 में उपचुनाव हुए। जिन अभ्यर्थियों ने त्यागपत्र दिया उनके लिए चुनाव अभियान सभी संयुक्त कार्यवाही समितियों के द्वारा चलाया गया। एक विचारबिन्दु था कि कांग्रेस और टीडीपी को इस ध्येय के साथ प्रतिबद्धता दर्षाते हुए अपने अभ्यर्थी मैदान में नहीं उतारने चाहिए परंतु इसे दोनों दलों के आलाकमानों ने नकार दिया। परिणाम यह रहा कि प्रान्तीय कांग्रेस दल के अध्यक्ष डी. श्रीनिवास सहित चार कांग्रेस अभ्यर्थियों और सभी टीडीपी प्रत्याषियों की जमानत जब्त हो गई। यह न केवल प्रत्याषियों बल्कि पृथक राज्य की माँग के पक्ष में एक प्रभावी जीत थी। इससे सुझाव मिलता है कि माँग लोकप्रिय जनचेतना में पहले से कहीं अधिक गहरे पैठ चुकी है। गैर राजनीतिक संयुक्त कार्यवाही समितियों जिन्हें उच्च न्यायसंगतता प्राप्त है, का योगदान महत्वपूर्ण है। यह वैधानिक गैर राजनीतिक नागरिक समिति निर्माणों और अवमूल्यित चुनावी राजनीति का मिलन है। प्रष्न शेष है कि तेलंगाना क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करने में कौनसी संस्कृति प्रभावी होगी।[4]

टीआरएस की उपचुनाव में सफलता को कांग्रेस और टीडीपी की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। टीआरएस ने इस विजय को तेलंगाना आंदोलन के जनमत संग्रह के रूप में देखा और पाया कि इस भावना से जनता को विष्वास में लिया जा सकता है और सहानुभूति की लहर में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने की संभावना बनती है।

उपचुनावों में कांग्रेस और टीडीपी के दयनीय प्रदर्षन को क्षेत्र में इन दलों में चल रहे गहरे संकट के रूप में देखा जा सकता है। चुनावी परिणामों के प्रति उनकी अनुक्रिया तेलंगाना प्रकरण पर उनके भ्रम को ओर स्पष्ट करती है। जैसे कि वे अपनी हार का कारण तेलंगाना पर उनके विचार के बिन्दुओं को लोगों तक पहुँचाने में अक्षमता को और टीआरएस प्रत्याषियों के प्रति लोकप्रिय सहानुभूति को मानते हैं। इसने टीआरएस के उस दावे को ओर उच्च बिन्दु पर पहुँचाया है कि यह विजय तेलंगाना राज्य की माँग के पक्ष में स्पष्ट जनमत है और इसलिए इस प्रकरण पर जनमत संग्रह की तरह स्वीकार की जानी चाहिए। यह कहना अतिषयोक्ति नहीं होगी कि यह चुनाव निर्णायक तौर पर दलीय राजनीति की गतिकी को प्रभावित करके तेलंगाना आंदोलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन बिन्दु हो सकता है। इसके साथ, यह कार्य की उन जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए अनुदेषनात्मक होगा जो कि यह चुनाव लाक्षणिक तौर पर प्रकट करता है।[5]

टीआरएस के चुनावी हथकंडे

टीआरएस की त्यागपत्र की तिकड़मों और निकट भविष्य में तेलंगाना को लेकर केंद्र के स्तर पर कोई विषिष्ट योजना नजर नहीं आने के कारण चुनाव परिणाम टीआरएस की दृष्टि से मिश्रित रहे परंतु टीआरएस ने इस चुनावी हथकंडे का परित्याग नहीं किया और इसे बार–बार प्रयोग में लिया।

टीआरएस का त्याग पत्र को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करने का अनुभव मिश्रित रहा है। 2006 में जब के. चंद्रषेखर राव ने करीमनगर से सांसद के रूप में त्याग पत्र दिया और पुनः चुनाव लड़ा, उन्होंने 2.15 लाख मतों की बहुमत से चुनाव जीता। यह तब हुआ जब तत्कालीन मुख्य मंत्री वाई. एस. राजषेखर रेड्डी के अधीन कांग्रेस ने निषेधरहित अभियान चलाया था। केसीआर न केवल तेलंगाना की माँग पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे अपितु तेलंगाना के लिए सषक्त लोकप्रिय अभिलाषा के प्रदर्षन के द्वारा दोनों प्रमुख दलों, कांग्रेस और टीडीपी को संकट में डालने में भी सफल रहे। उन्होंने 2007 में टीआरएस के 16 विधायकों के त्याग पत्र के साथ इसे दोहराने

का प्रयत्न किया। पारिणामिक उपचुनाव में केवल सत्तासीन 10 विधायक ही पुनः चुने गए जबकि चार ने कांग्रेस के पक्ष में और दो ने टीडीपी के पक्ष में अपनी सीट खो दी। 2008 में सांसद के रूप में केसीआर के दूसरे त्यागपत्र के पष्चात् हुए उपचुनाव में वे केवल लगभग 15000 मतों के न्यून अंतर से विजयी हुए। मतदाता की थकान और टीआरएस के चुनावी तिकड़मों के प्रति लोकप्रिय असंतोष बिल्कुल प्रमाणिक था।[6]

चुनावी परिणामों की व्याख्या

उप चुनावों की एक प्रकार से व्याख्या करने पर लगता है कि त्यागपत्र के बाद पुनः उसी विधानसभा क्षेत्र से जीतना कठिन हो जाता है परंतु टीआरएस के बहुसंख्य विधायकों को सफलता मिली अतः इसके परिणामस्वरूप राज्य के भारी दलों कांग्रेस और टीडीपी ने टीआरएस से गठबंधन की संभावनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक स्तर पर टीआरएस को अवसरवादी कहने वाली संस्थाओं ने भी अपने रुख में भारी परिवर्तन किया।

चुनावी परिणाम की दो कारणों से उपादेयता है। प्रथम, इसने तेलंगाना में लोकप्रिय मनोभाव के बारे में स्पष्ट संदेष भेजा है जहाँ पृथक राज्य के लिए समर्थन पर राजनीतिक ध्रुवीकरण ने अभी तक इस क्षेत्र में प्रभावी रहे दो प्रमुख दलों के चुनावी संभावनाओं को भारी हानि पहुँचाई है। द्वितीय, प्रमुख रूप से परिस्थितियों के कारण, वे सामाजिक शक्तियाँ जो पहले टीआरएस की निंदा करती थी और यहाँ तक कि टीआरएस से वैचारिक दृष्टि से विपरीत थी, उन्होंने भी आवष्यक लगा कि गंभीर सामाजिक और वैचारिक सीमाओं के उपरांत भी वे टीआरएस के साथ हों[7]

तेलंगाना आंदोलन में अन्य दलों की स्थिति

तेलंगाना आंदोलन के पक्ष में टीआरएस के अतिरिक्त कांग्रेस और टीडीपी ने भी समर्थन दिया। व्यावहारिक स्तर पर जन आंदोलनों का आयोजन किया गया परंतु जिस भावना के साथ कांग्रेस और टीडीपी ने इस कार्य को संपादित किया उससे दोनों दलों को एक–दूसरे को पतित करने का प्रयास लगा। जनता को दोनों दलों की भावनाओं में प्रतिबद्धता और सत्यता का अभाव लगा और दोनों दलों को 2014 के प्रथम विधानसभा चुनावों में तेलंगाना राज्य में अत्यंत निराषाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा और 2018 के चुनावों ने इन दोनों दलों की कमर तोड़ कर ही रख दी क्योंकि एक बहुदलीय गठबंधन की रचना के बाद भी चुनाव परिणाम इनके अनुकूल नहीं रहे। नवीन राज्य के निर्माण में केंद्र स्तर पर कांग्रेस सरकार के निर्णय लेने के उपरांत भी कांग्रेस को पराजय ही मिली।

तेलंगाना आंदोलन संसदीय राजनीतिक दलों की बेईमानी और जोड़–तोड़ की राजनीति को स्पष्ट सामने लाता है। दो मुख्य राजनीतिक दलों – कांग्रेस और टीडीपी और अन्य अनेक लघुतर दलों ने तेलंगाना की माँग का खुला समर्थन किया और यहाँ तक कि दल में संकल्प और सहमति के बिना 2009 के चुनावों के दौरान इसके समर्थन में अभियान भी चलाया। यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें प्रत्येक की आषा दूसरे की बेईमानी पर टिकी हुई थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि जैसे ही पृथक राज्य की माँग ने जोर पकड़ा, प्रत्येक दल ने दूसरे पर वादे को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उदाहरण के लिए, चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा के मंच पर स्पष्ट रूप से कहा कि उनका दल पृथक राज्य के विधेयक के पक्ष में झिझक के बिना मतदान करेगा, यदि कांग्रेस दल इस विधेयक को लाने का साहस करे। मुख्यमंत्री के. रोसय्या ने दलों के विचार जानने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में टीडीपी ने अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया यदि कांग्रेस इस प्रक्रिया को प्रारंभ करे। परंतु जिस मिनट गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा की कि तेलंगाना राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, टीडीपी ने यह तर्क देते हुए खुद को पीछे कर लिया कि उचित वाद–विवाद के बिना ही 9 दिसंबर 2009 मध्यरात्रि को घोषणा कर दी गई। वास्तव में, वादविवाद की माँग या तो तब उठानी चाहिए थी जब प्रकरण राज्य विधानसभा में आया था अथवा तब उठानी चाहिए थी जब सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। इस प्रकरण पर पूर्ण विपरीत कदम ने प्रकट किया कि टीडीपी ने वादा नहीं निभाया, टीडीपी स्पष्ट और उदग्र रूप से इस प्रकरण पर बँटी हुई है और दोनों क्षेत्रों में नेता पूर्ण रूप से विपरीत कथन कहते रहे हैं यद्यपि वे समान राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस प्रकरण पर टीडीपी का कोई स्पष्ट दृढ़निर्णय था अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो भी दोनों क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट नहीं था। जब पूछा गया कि दल का क्या निर्णय है तो वरिष्ठ टीडीपी नेताओं ने निजता से बताया कि उन्हें उनके नेता द्वारा सलाह दी गई है कि वे इस विषय पर उसी निर्णय का समर्थन करें जो कांग्रेस ने प्रस्तावित किया। उन्होंने आगे कहा कि जैसे कांग्रेस दल का निर्णय विभाजित है, वैसा ही प्रकरण टीडीपी के साथ है। यदि सोनिया गाँधी चुप हैं तो उनके नेता चंद्रबाबू नायडू भी चुप रहेंगे। यदि कांग्रेस तेलंगाना की माँग के समक्ष झुकती है तो टीडीपी भी सम्मानपूर्वक इसके स्वीकार करेगी[8]

केसीआर का स्वर्णिम काल

2014 में केसीआर तेलंगाना राज्य के मेडक जिले के गजवेल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और 19218 मतों से विजयी हुए। 16–5–2014 को वह मेडक संसदीय क्षेत्र से 397029 मतों से जीते। तेलंगाना में एक दषक से अधिक समय तक पृथक राज्य के अभियान को चलाने वाली टीआरएस 17 संसदीय सीटों में से 11 और 119 विधानसभा सीटों में से 63 पर जीत हासिल कर सबसे बड़ा दल बनी और इस मत प्रतिषत सर्वाधिक रहा। केसीआर ने 2 जून 2014 को 12.57 मध्याह्न बजे तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

7 दिसंबर 2018 को तेलंगाना के द्वितीय विधानसभा चुनावों में टीआरएस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेलंगाना जन समिति, तेलगुदेषम पार्टी और सीपीआई के गठबंधन महाकुटमी को हरा कर एक बार फिर तेलंगाना में सत्ता हासिल की है। मुख्यमंत्री के. चन्द्रषेखर राव ज्योतिष, अंकषास्त्र और वास्तु में विष्वास रखते हैं।

निष्कर्ष

के. चन्द्रषेखर राव एक सफल राजनीतिज्ञ हैं जिनको तेलंगाना राष्ट्र समिति के गठन के समय कमतर आंका गया था परंतु उन्होंने जबरदस्त राजनीतिक दाव–पेंचों से अपने से कहीं शक्तिषाली केंद्र को झुका कर तेलंगाना को राज्य के रूप में मान्यता दिलवाई। लगभग नगण्य लोकसभा सीट जीतकर तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में केंद्र को कमजोर होना टीआरएस के भाग्य को ऊँचाइयों के नवीन मुकाम तक ले गया जहाँ पहुँयने के उपरान्त टीआरएस ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जनता की नब्ज को एक कुषल राजनीतिज्ञ बेहतर समझ सकता है। तेलंगाना राज्य के सभी तबकों के लिए मनोहारी योजनाएँ लाकर के. चन्द्रषेखर राव लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। वर्तमान परिवेष में तेलंगाना की राजनीति में टीआरएस का भविष्य लगभग सुरक्षित और संरक्षित है।

संदर्भ

1. जी. हरगोपाल द तेलंगाना पीपल्ज मूवमेंट : दी अनफोल्डिंग पोलिटिकल कल्चर इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली,

वोल्यूम 45, संख्या 42 अक्टूबर 16–22, 2010, पृष्ठ संख्या 57
2. तेलंगाना डिमांड इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वोल्यूम 43, संख्या 46 नवंबर 15–21, 2008, पृष्ठ संख्या 7
3. बसु, दुर्गादास भारत की सांवैधानिक विधि प्रेंटिस– हाल ऑव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ संख्या 23
4. जी. हरगोपाल द तेलंगाना पीपल्ज मूवमेंट : दी अनफोल्डिंग पोलिटिकल कल्चर इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वोल्यूम 45, संख्या 42 अक्टूबर 16–22, 2010, पृष्ठ संख्या 60
5. के. श्रीनिवासुलु एंड डी. सत्यनारायणा बाई इलेक्षन्स एंड तेलंगाना एजिटेषन इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वोल्यूम 45, संख्या 33 अगस्त 14–20, 2010, पृष्ठ संख्या 12
6. के. श्रीनिवासुलु एंड डी. सत्यनारायणा बाई इलेक्षन्स एंड तेलंगाना एजिटेषन इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वोल्यूम 45, संख्या 33 अगस्त 14–20, 2010, पृष्ठ संख्या 13
7. के. श्रीनिवासुलु एंड डी. सत्यनारायणा बाई इलेक्षन्स एंड तेलंगाना एजिटेषन इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वोल्यूम 45, संख्या 33 अगस्त 14–20, 2010, पृष्ठ संख्या 14
8. जी. हरगोपाल द तेलंगाना पीपल्ज मूवमेंट : दी अनफोल्डिंग पोलिटिकल कल्चर इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वोल्यूम 45, संख्या 42 अक्टूबर 16–22, 2010, पृष्ठ संख्या 58–59